भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले—1993 के दौरान किया गया विदेशी व्यापार

*496. **श्रीमती चन्द्रिका अभिनन्दन जैन:** क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1993 में हुए भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले के दौरान अनुमानत: कितना विदेशी व्यापार हुआ;

(ख) इस व्यापार के अंतर्गत देश द्वारा अर्जित की गई विदेशी मुद्रा का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस मेले के आयोजन के दौरान विदेशी निवेशकों, अनिवासी भारतीयों तथा विदेशी संस्थानों के साथ देश की विभिन्न परियोजनाओं में निवेश से संबंधित किसी समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं;

(घ) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या इन निवेशों से महाराष्ट्र और गुजरात राज्यों को लाभ होने की संभावना है; और

(च) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) और (ख) भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला 1993 के कुछ भागीदारों से प्राप्त सूचना के आधार पर इस मेले में हुए व्यापार की तथा गंभीर व्यापारी पूछताछ की धनराशि रुपए 403 करोड़ होने का अनुमान है । इस मेले हेतु स्थान के किराए के रूप में विदेशी प्रदर्शकों से 1,11,950 संयुक्त राज्य अमरीकी डालर की विदेशी मुद्रा प्राप्त हुई है ।

(ग) और (घ) ऐसी रिपोर्ट मिली है कि 47 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर हुए थे और "टेकमार्ट" 1993 से प्राप्त रिपोर्टों के के आधार पर यह पता चला कि विदेशी भागीदारों के साथ 5 संयुक्त औद्योगिक उद्यम लगाने के बारे में बातचीत चल रही थी । "टेकमार्ट" 1993 भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला 1993 का ही एक अंग था और इसका आयोजन राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम ने "यूनिडो" के सहयोग से किया था ।

(ङ) और (च) महाराष्ट्र और गुजरात राज्यों को निवेशों के कारण क्या लाभ हुआ या हो सकता है इस बारे में कोई निश्चित सूचना नहीं मिली है ।

Legislation on Rural Labour

*497. SHRI GURUDAS DAS GUPTA : Will the Minister of LABOUR be pleased to state by when Government intend to bring Central Legistation on rural labour as recommended by the Rural Commission for Rural Labour?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE (SHRI PABAN SINGH GHATOWAR) : The National Commis sion on Rural Labour has not made any recommendation for a Central Legislation for Rural Labour as such. Its recommendation for a Central Legislation for Agricultural workers is at an advanced stage of consideration based on consultations with State Governments.

देश में केन्द्र द्वारा प्रायोजित परियोजनाएं

*498. **श्री राम जेठमलानी :**

श्री वीरेन्द्र जे. शाह :

क्या **योजना और कार्यान्वयन कार्यान्वयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में मार्च, 1994 में केन्द्र सरकार द्वारा प्रायोजित कुल कितनी परियोजनाएं निर्माणाधीन थीं;

(ख) इनमें से कितनी परियोजनाएं अपने मूल निर्धारित समय में पूरी की जा रही हैं;

(ग) इन परियोजनाओं में से कितनी परियोजनाएं विदेशी वित्तीय संस्थाओं के सहयोग से निर्माणाधीन हैं तथा इन संस्थाओं द्वारा कुल कितनी राशि इन परियोजनाओं के निर्माण हेतु स्वीकृत की गई है;

(घ) क्या यह भी सच है कि पूर्व निर्धारित शर्तों के अनुसार इस स्वीकृत राशि का परियोजना के निर्माण में उपयोग न कर पाने के कारण सरकार को वर्ष 1993-94 के दौरान वचनबद्धता प्रभार का भुगतान करना पड़ा है; और

(ङ) यदि हां, तो ऐसे वचनबद्धता प्रभार की राशि कितनी है ?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री निरिश्वर गोस्वामी) : (क) 1 जनवरी, 1994 को 20 करोड़ रुपए और उससे अधिक लागत की कुल 367 परियोजनाएं निर्माणाधीन थीं ।

(ख) कार्यक्रम कार्यान्वयन विभाग की प्रबंधन प्रणाली की 367 परियोजनाओं में से 25 परियोजनाओं के दिसम्बर, 1993 तक पूरे हो जाने की सूचना है और 77 परियोजनाओं के मार्च, 1994 तक पूरे हो जाने की संभावना है । बाकी 265 परियोजनाओं में से 128 परियोजनाएं अपने मूल कार्यक्रम के अनुसार चल रही हैं ।

(ग) मामला वित्त मंत्रालय के कार्यक्षेत्र के अंतर्गत आता है । इस संबंध में उनके द्वारा प्रस्तुत किया गया एक विवरण सदन पटल पर रखा जाता है ।

[देखिए परिशिष्ट 170, अनुबन्ध संख्या 103]

(घ) और (ङ) जी हां, वर्ष 1993-94 के दौरान बाह्य सहायता के अंतर्गत आने वाली केन्द्रीय परियोजनाओं के संबंध में वचनबद्धता प्रभारों की कुल राशि 32.53 करोड़ रुपए है ।

Indian Workters and Labourers gonig out at World Trade Organisations

*499. SHRI RAMNATH KOVIND' : Will the Minister of LABOUR be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Government are making a bargain by accepting at World Trade Organisations, the proposal of sending India's workers and labourers out;

(b) if so, what are the details of this proposal and what benefit will India accrue therefrom;

(c) whether Government have taken up any study about the prospects of our workers in foreign countries skill-wise and class-wise;

(d) if so, what are the details thereof;

(e) if not, why was such study not considered necessary before making a pro-posa!; and

(f) whether such a sell-out of India's labour force will not lower the country's prestige ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE (SHRI PABAN SINGH GHATOWAR : (a) to (f) In the final stages of preparation for the concluding Ministerial meeting of the Uruguay Round at Marrakesh, the United States proposed the inclusion of the following paragraph in the Marrakesh Declaration :